



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 2019/आश्विन 9, 1941

No. 353]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019/ASVINA 9, 1941

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी (आठवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 5)

सं. 116-4/2019-एनएसएल-II.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (iii) तथा (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्वारा दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी (आठवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 5) कहा जाएगा।
(2) यह विनियम दिनांक 11 नवम्बर, 2019 से लागू होंगे।
- दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) (इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 2 में, खंड (ढ) में "प्रत्येक सफल पोर्टिंग" शब्दों के स्थान पर "पोर्टिंग अनुरोध को संसाधित करना" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (7) के स्थान पर निम्नवत उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः—
“(7) प्राप्तकर्ता आपरेटर, मोबाइल नम्बर के प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध के लिए मोबाइल नम्बर सेवा प्रदाता को प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का भुगतान करेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किया जाएगा।
(8) प्राप्तकर्ता प्रचालक, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सेवा की गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करेगा।”
- विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (1) में,—
(क) उपबंध (ग) में “खंड (ख) के तहत दाता प्रचालक” शब्दों के पश्चात् और “विनियम 10 अथवा समाप्त हो जाने” शब्दों से पूर्व, शब्द “उप-विनियम (2) के” को अंतःस्थापित किया जाएगा।
(ख) उपबंध (ग) के पश्चात् अनंतिम में “खंड (ख) के तहत दाता प्रचालक” शब्दों के पश्चात् और “विनियम 10 अथवा समाप्त हो जाने” शब्दों से पूर्व, शब्द “उप-विनियम (2) के” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

एस. के. गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./241/19]

टिप्पण 1: मूल विनियमों को दिनांक 23 सितम्बर, 2009 को अधिसूचना संख्या 116-4/2009-एमएन (खंड II) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में प्रकाशित किया गया था और निम्नवत के अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया था:—

- (i) दिनांक 28 जनवरी, 2010 (2010 का 1) की अधिसूचना संख्या 116-1/2010।
- (ii) दिनांक 24 नवम्बर, 2010 (2010 का 5) की अधिसूचना संख्या 116-1/2010।
- (iii) दिनांक 08 जून, 2012 (2012 का 16) की अधिसूचना संख्या 116-5/2012।
- (iv) दिनांक 19 सितम्बर, 2012 (2012 का 19) की अधिसूचना संख्या 116-5/2012।
- (v) दिनांक 22 जुलाई, 2013 (2013 का 9) की अधिसूचना संख्या 116-4/2013।
- (vi) दिनांक 25 फरवरी, 2015 (2015 का 03) की अधिसूचना संख्या 116-19/2014।
- (vii) दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 (2018 का 9) की अधिसूचना संख्या 116-6/2017-एनएसएल-II।
- (viii) दिनांक 12 जून, 2019 (2019 का 1) की अधिसूचना संख्या 116-6/2017-एनएसएल-II, खंड-II।
- (ix) दिनांक 27 सितम्बर, 2019 (2019 का 3) की अधिसूचना संख्या 116-6/2017-एनएसएल-II, खंड-III।

टिप्पण 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन, इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 23 सितम्बर, 2009 को देश में इंटर-सर्किल मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के कार्यान्वयन हेतु मूलभूत व्यापार प्रक्रिया ढांचे को निर्धारित करते हुए दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किए थे। दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को हरियाणा सेवा क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर एमएनपी सुविधा आरंभ की गई थी और इसे दिनांक 20 जनवरी, 2011 को संपूर्ण देश में विस्तार दिया गया था। आरंभ में एमएनपी सुविधा, केवल लाइसेंस सेवा क्षेत्र के भीतर उपलब्ध थी। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में अंतर्विष्ट “एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी” उपबंधों के अनुरूप, पूर्ण एमएनपी को दिनांक 03 जुलाई, 2015 को लागू किया गया था।
2. दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियम, 2009 (2009 का 8) के मूल विनियमों में दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2009 का 9) जारी किया जिन्हें आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से छह माह पश्चात् लागू किया जाना था। इन संशोधन विनियमों के माध्यम से विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के सृजन हेतु प्रणाली में बड़े बदलाव का प्रावधान किया गया था। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपी) द्वारा यूपीसी के सृजन हेतु अर्हता शर्तों के पूर्व-अधिप्रमाणन से संशोधित ढांचे में निर्बाध पोर्टिंग सुनिश्चित होगी, इस प्रकार, पोर्टिंग की प्रक्रिया तीव्र तथा मोबाइल सब्सक्राइबर्स के लिए अधिक सुविधाजनक होगी।
3. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 के कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा को दिनांक 12 जून, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से 13 जून, 2019 से बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2019 कर दिया गया था और दिनांक 27 सितम्बर, 2019 कार्यान्वयन की तिथि को 30 सितम्बर, 2019 से बढ़ाकर 11 नवम्बर, 2019 कर दिया गया था। इन अधिसूचनाओं के माध्यम से दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) के विनियम 1 के उप-विनियम (2) में संशोधन कर दिया गया है।
4. प्राधिकरण ने दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) के व्याख्यात्मक ज्ञापन के माध्यम से उल्लेख किया था कि संबद्ध लागतों के पहलूओं पर, प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभारों की समीक्षा को पृथक रूप से कार्यवाही की जाएगी और इसमें एमएनपीएसपी द्वारा यूपीसी सृजन करने और विभिन्न चरणों पर एसएमएस द्वारा भेजे जाने की लागत भी शामिल होगी।
5. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2019 (तत्पश्चात्, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को अद्यतन किया गया) को “मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी हेतु प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और अन्य संबंधित प्रभारों की समीक्षा” पर परामर्श पत्र जारी किया और इस मुद्दे पर भी टिप्पणियां आमंत्रित की गईं कि क्या प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का परिकलन हेतु, एमएनपीएसपी द्वारा प्राप्त किए गए एमएनपी अनुरोधों की कुल संख्या अथवा सफलतापूर्वक पोर्ट किए गए नम्बरों की संख्या को लिया जाना चाहिए?
6. आंकड़ों का विश्लेषण करने पर, प्राधिकरण ने पाया कि कुल पोर्टिंग अनुरोधों और सफलतापूर्वक पोर्टिंग के बीच अंतर पिछले कुछ वर्षों के दौरान कम हो रहा है और सातवें संशोधन के लागू होने पर इसमें और कमी होने की संभावना है। इसके अलावा, एमएनपीएसपी को असफल पोर्टिंग अनुरोधों पर भी लागत को वहन करना पड़ता है। इसके अलावा, अनेक मामलों में किसी पोर्टिंग अनुरोध का असफल हो जाना एमएनपीएसपी के नियंत्रण से परे कारणों के चलते भी हो सकता

है। जबकि, प्रतिक्रिया में प्राप्त टिप्पणियों में अधिकांश हितधारकों ने प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का निर्धारण करने हेतु, एमएनपी अनुरोधों की कुल संख्या को अपनाने का सुझाव दिया है। तदनुसार, प्राधिकरण ने प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार निर्धारण करने हेतु प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध को ध्यान में रखने का निर्णय लिया है। इसलिए, दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) के विनियम 8 के उप-विनियम (7) में संशोधन किया गया है।

7. इस संशोधन नियमों के माध्यम से उपयुक्त संशोधन को शामिल करते हुए, मूल विनियम के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के अन्तिम और उपबंध (ग) को विनियम 10 के उप-विनियम (2) के उपबंध (ख) को उचित रूप से जोड़ दिया गया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

TELECOMMUNICATION MOBILE NUMBER PORTABILITY (EIGHTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2019 (5 of 2019)

No. 116-4/2019-NSL-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36, read with sub-clauses (i), (iii) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), namely:—

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability (Eighth Amendment) Regulations, 2019 (5 of 2019).
- (2) These regulations shall come into force from the 11th November, 2019.
2. In regulation 2 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) (hereinafter referred to as principal regulations), in clause (n) for the words “each successful porting” the words, “processing the porting request” shall be substituted;
3. In regulation 8 of the principal regulations, for sub-regulation (7), the following sub-regulations shall be substituted, namely: —

“(7) The Recipient Operator shall be liable to pay Per Port Transaction charge for each porting request of the mobile number to the Mobile Number Portability Service provider as notified by the Authority from time to time.

(8) The Recipient Operator shall be liable to comply with the Quality of Service parameters, as specified by the Authority from time to time.”
4. In regulation 11 of the principal regulations, in sub-regulation (1),—
 - (a) in clause (c), after the words “Donor Operator under clause (b)” and before the words “of regulation 10 or the expiry” the words, “of sub-regulation (2)” shall be inserted;
 - (b) in proviso after the clause (c), after the words, “Donor Operator under clause (b)” and before the words, “of regulation 10 or the expiry” the words, “of sub-regulation (2)” shall be inserted;

S. K. GUPTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./241/19]

Note 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification No. 116-4/2009-MN (Vol.II) dated 23rd September, 2009 and amended *vide*:

- (i) Notification No. 116-1/2010 dated 28th January, 2010 (1 of 2010)
- (ii) Notification No. 116-1/2010 dated 24th November, 2010 (5 of 2010)
- (iii) Notification No. 116-5/2012 dated 8th June, 2012 (16 of 2012)
- (iv) Notification No. 116-5/2012 dated 19th September, 2012 (19 of 2012)
- (v) Notification No. 116-4/2013 dated 22nd July, 2013 (9 of 2013)
- (vi) Notification No. 116-19/2014 dated 25th February, 2015 (03 of 2015)
- (vii) Notification No. 116-6/2017-NSL-II dated 13th December, 2018 (9 of 2018)
- (viii) Notification No. 116-6/2017-NSL-II.Vol.II dated 12th June, 2019 (1 of 2019)
- (ix) Notification No. 116-6/2017-NSL-II.Vol.III dated 27th September, 2019 (3 of 2019)

Note 2: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of these regulations.

Explanatory Memorandum

1. The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) dated 23rd September, 2009 laying down the basic business process framework for implementation of intra-circle Mobile Number Portability (MNP) in the country. Facility of MNP was launched in Haryana service area on 25th November 2010 on pilot basis and the same was extended to the entire country on 20th January 2011. Initially, the MNP facility was available within the licensed service area only. However, in accordance with the provisions contained in the National Telecom Policy- 2012 regarding “One Nation–Full Mobile Number Portability”, full MNP was implemented w.e.f. 3rd July 2015.
2. On 13th December 2018, TRAI had issued the Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018 (9 of 2018), to the principal regulations of Telecommunication Mobile Number Portability (MNP) Regulations 2009 (8 of 2009) to come into force after six months from the date of their publication in the official Gazette. Through these amendment regulations a major shift in the mechanism for generating Unique Porting Code (UPC) has been provisioned. Pre-validation of eligibility conditions for generation of UPC by the Mobile Number Portability Service Provider (MNPSP) shall ensure smooth porting in revised framework; thus, making the porting process faster and convenient to the mobile subscribers.
3. Considering the preparedness of Telecom Service Providers and Mobile Number Portability Service providers, the timeline for implementation of Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018, was extended from 13th June 2019 to 30th September 2019 vide Notification dated 12th June, 2019; and further vide Notification dated 27th September, 2019 the date of implementation has been extended from 30th September 2019 to 11th November, 2019. Through these Notifications, sub-regulation (2) of regulation 1 of the Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018 (9 of 2018) has been amended.
4. The Authority through the Explanatory Memorandum of the Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018 (9 of 2018) had mentioned that on the aspects of the associated costs, review of Per Port Transaction Charges shall be taken up separately and these charges shall include the cost of generating UPCs by MNPSPs and sending SMSs at various stages.
5. TRAI issued Consultation Paper on ‘Review of Per Port Transaction Charge and Other Related Charges for Mobile Number Portability’ dated 22nd February 2019 (subsequently updated on 1st April, 2019) for the comments of stakeholders and comments were inter-alia sought on whether the total number of MNP requests received by MNPSP or successfully ported numbers be considered while calculating ‘Per Port Transaction Charge’?
6. Upon analysis of the data, the Authority observed that the gap between total porting requests and successful porting has been reducing over the years and is likely to reduce further after the 7th Amendment comes into force. Besides, the MNPSPs have to incur costs even on unsuccessful porting requests. Further, in many cases, the failure of a porting request could be due to reasons beyond the control of the MNPSPs. Through the comments received in response, most of the stakeholders have also suggested to consider total number of port requests. Accordingly, the Authority decided to take each porting request into consideration for determining the Per Port Transaction Charge. Therefore, sub-regulation (7) of regulation 8 of the Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018 (9 of 2018) has been amended.
7. In order to link appropriately the proviso and clause (c) of sub-regulation (1) of the regulation 11 of the principal regulations, with the clause (b) of the sub-regulation (2) of regulation 10, of the principal regulations, the appropriate amendment has been incorporated through this amendment regulations.